www.summerexpress.in
समर प्राइम 3
26 जनवरी 2026
समर एक्सप्रेस

विदेशों में छिपे भारत के 71 वांछित भगोड़े, एक दशक में सबसे अधिक; 2024-25 में 27 को लाए वापस

समर न्यूज़ | नई दिल्ली

सरकार की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024–25 के दौरान भारत को वांछित 71 भगोड़े विदेशों में मौजूद थे, जबकि इसी अवधि में दूसरे देशों द्वारा तलाशे जा रहे 203 व्यक्तियों का भारत में पता लगाया गया। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशों में मौजूद भारतीय भगोड़ों की संख्या पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक रही।

रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कुल 27 वांछित व्यक्तियों या भगोड़ों को विभिन्न देशों से भारत लाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय जांच ब्यूरो की भूमिका अहम रही, जो इंटरपोल के लिए भारत में नोडल एजेंसी—नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में काम करती है। मंत्रालय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए इन मामलों में लगातार प्रगति की जा रही है।

विदेशों को भेजे गए 74 न्यायिक अनुरोध

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच भारत की ओर से 74 'लेटर रोगेटरी' विभिन्न देशों को भेजे गए। इनमें से 54 अनुरोध सीबीआई मामलों से जुड़े थे, जबकि 20 राज्य पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित थे। लेटर रोगेटरी न्यायिक सहायता के लिए विदेशी सरकारों को भेजे जाने वाले आधिकारिक अनुरोध होते हैं। एजेंसियों ने बताया कि इस अवधि में 47 मामलों में अनुरोध पूरी तरह लागू हुए, जबकि 29 में आंशिक कार्रवाई के बाद उन्हें बंद या वापस ले लिया गया। 31 मार्च 2025 तक कुल 533 ऐसे अनुरोध विभिन्न देशों के पास लंबित थे। इनमें 276 सीबीआई और 257 राज्य पुलिस अथवा अन्य केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े थे। इसके अलावा विदेशी जांच एजेंसियों से सहयोग के लिए 32 अंतरराष्ट्रीय अनुरोध भारत को भी प्राप्त हुए।

▪ इंटरपोल के माध्यम से नोटिस जारी... *रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष के दौरान एनसीबी-इंडिया ने इंटरपोल के जरिए कई तरह के नोटिस जारी किए। इनमें 126 रेड नोटिस, 89 ब्लू नोटिस, 24 येलो नोटिस, सात ब्लैक नोटिस और एक ग्रीन नोटिस शामिल थे। रेड नोटिस का उद्देश्य किसी आरोपी की तलाश और अस्थायी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करना होता है, जबकि ब्लू नोटिस पहचान और गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। येलो नोटिस लापता लोगों से संबंधित होते हैं और ब्लैक नोटिस अज्ञात शवों की पहचान के लिए जारी किए जाते हैं। ग्रीन नोटिस सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के बारे में चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।*

सीबीआई ने अपने वैश्विक संचालन केंद्र के माध्यम से विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय कर कई भगोड़ों और अपराधियों का पता लगाया। जैसे ही किसी वांछित व्यक्ति का स्थान सामने आता है, एजेंसी गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संबंधित देशों के इंटरपोल कार्यालयों के साथ मिलकर प्रत्यर्पण या वापसी की प्रक्रिया शुरू करती है।

▪ नागरिकता मामलों और पासपोर्ट रिकॉर्ड पर भी कार्रवाई... *अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच सीबीआई की इंटरपोल इकाई ने भारतीय नागरिकता छोड़ने से जुड़ी 22,200 से अधिक अर्जियों पर कार्रवाई कर अपनी टिप्पणियां दीं। इसके साथ ही इंटरपोल के चोरी और गुमशुदा यात्रा दस्तावेजों के डेटाबेस से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई।*

एमईएम ने बदली इलाज की दिशाः इमरजेंसी में अब वहीं होता है फैसला

हस्ताक्षर

पायल मोहिंद्रा

एक समय था जब फर्स्ट-एड के नाम पर घर या वाहन में केवल रुई और कुछ दवाइयाँ रख ली जाती थीं, लेकिन बदलते दौर के साथ चिकित्सा व्यवस्था भी आधुनिक हो गई है। आज फर्स्ट-एड की जगह बुनियादी जीवन रक्षक प्रणाली यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस)ने ले ली है, जिसे किसी भी आपात स्थिति में मरीज की जान बचाने की पहली और सबसे अहम कड़ी माना जाता है।

बीएलएस और इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं में आए बदलावों पर सुपर स्पेशलिस्ट इमरजेंसी मेडिसन चिकित्सक डॉ. दविंद्र सिंह बताते हैं कि भारत में इमरजेंसी मेडिसन एक अलग विशेषज्ञता के रूप में 17 वर्ष पहले शुरू हुई। इससे पहले गंभीर मरीजों को प्राथमिक इलाज के बाद सीधे आईसीयू में भेज दिया जाता था, लेकिन अब मरीज को पहले इमरजेंसी विभाग में लाया जाता है। वहीं उसकी स्थिति का मूल्यांकन कर यह तय किया जाता है कि उसे वार्ड में भर्ती करना है, आईसीयू की जरूरत है, डिस्चार्ज किया जा सकता है या भर्ती की आवश्यकता ही नहीं है।

रक्तस्राव की स्थिति में उन्होंने बताया कि सबसे पहले साफ कपड़े या पट्टी से घाव पर लगातार दबाव बनाए रखें और घायल अंग को संभव हो तो हृदय से ऊंचाई पर रखें। खून रुकने के बाद पट्टी बांधकर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जलने की स्थिति में जले हिस्से को 10 से 15 मिनट तक साफ बहते पानी के नीचे ठंडा करना चाहिए, जिससे जलन और दर्द कम होता है। बर्फ सीधे त्वचा पर लगाने से बचना चाहिए और हल्की बर्न या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर मरीज को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए।

नाक, कान या गले में कोई वस्तु फंस जाए तो घबराने के बजाय उसे खुद निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि गले में खाना अटकने से सांस लेने में दिक्कत हो, तो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा हाइमलिक मैन्युवर किया जा सकता है, अन्यथा तुरंत अस्पताल पहुंचाना सबसे सुरक्षित उपाय है।

सीपीआर (कार्डियो-पल्मोनरी रिससिटेशन) के बारे में डॉ. दविंद्र ने कहा कि सबसे पहले अपनी और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा एंबुलेंस को कॉल करें। सांस और नाड़ी की जांच करें, कलाई की बजाय गर्दन की कैरोटिड आर्टरी पर दो उंगलियों से पल्स देखी जानी चाहिए। मरीज को सीधी सतह पर लिटाकर छाती के बीचों-बीच 30 बार दबाव दें और प्रशिक्षित होने पर दो रेस्क्यू ब्रीथ दें। यह प्रक्रिया मदद आने तक जारी रखें।

बीएलएस ट्रेनिंग अब स्कूलों, कॉलेजों, फैक्ट्रियों और संस्थानों में भी दी जा रही है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर मरीज को बाईं करवट लिटाएं, आसपास की कठोर वस्तुएं हटा दें और तुरंत मेडिकल सहायता बुलाएं। अंत में उन्होंने अपील की कि हर घर, वाहन, स्कूल और कार्यालय में फर्स्ट-एड किट जरूर रखें, क्योंकि पुलिस नियमों के अनुसार वाहन में किट न होने पर चालान का प्रावधान भी है।

प्रयागराज में अस्थायी गोशालाएं बंद, बढ़ेंगे वृहद स्थायी गो आश्रय स्थल

कम क्षमता वाली गोशालाओं को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा बंद, 25 हजार मवेशी वृहद स्थायी केंद्रों में स्थानांतरित होंगे

एजेंसी | प्रयागराज

बेसहारा मवेशियों से किसानों को राहत दिलाने के लिए बनाई गई अस्थायी गोशालाओं को अब चरणबद्ध तरीके से बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। उनकी जगह बड़े और स्थायी गो आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पशुपालन विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और सबसे पहले कम क्षमता वाली गोशालाओं को बंद कर वहां मौजूद पशुओं को वृहद स्थायी केंद्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक पहले 30 मवेशियों वाली दो अस्थायी गोशालाएं बंद कर दी गई हैं। अब 50 पशुओं की क्षमता वाली अस्थायी गोशालाओं को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में मौजूद 121 अस्थायी गोशालाओं को एक-एक कर समाप्त किया जाएगा और वहां के सभी पशुओं को स्थायी केंद्रों में भेजा जाएगा।

वर्ष 2019 में शासन ने गांव-गांव अस्थायी गोशालाएं खोलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद जिले के विभिन्न ग्राम सभाओं में ये केंद्र बनाए गए थे। वर्तमान में गंगापार और यमुनापार क्षेत्रों में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की 121 गोशालाएं संचालित हैं, जिनमें 25 हजार बेसहारा मवेशी रखे गए हैं। इनमें कोरांव के लतीफपुर, होलागढ़ के उमरिया बादल और मांडा के देवरी में बने तीन वृहद गो आश्रय स्थल पहले से स्थायी रूप में काम कर रहे हैं। स्थायी गोशालाओं में सुविधाएं अस्थायी केंद्रों की तुलना में बेहतर होती हैं। एक केंद्र में 400 से 500 मवेशियों को रखा जा सकता है। कई अस्थायी गोशालाओं में कम पशु हैं, संचालन खर्च बढ़ रहा है। स्थायी गोशालाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भूमि मानक में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां एक हेक्टेयर भूमि अनिवार्य थी, अब इसे घटाकर आधा हेक्टेयर कर दिया गया है ताकि भूमि की कमी बाधा न बने। इससे एक ओर पशुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं गोशालाओं की संख्या घटने से सरकार के खर्च में भी कुछ कमी आने की उम्मीद है।

इस बीच जसरा के रेरा, शंकरगढ़ के सोनबरसा और उरवा के पलानीपुर उपरहार में नए वृहद गो आश्रय स्थल निर्माणाधीन हैं। कोरांव के बसहरा में स्थायी गोशाला बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जबकि बारा तहसील क्षेत्र में तीन और बड़े केंद्र प्रस्तावित हैं।

61 हजार से अधिक मकानों का निर्माण पूरा, 30 शहरों में 145 परियोजनाएं सक्रिय

अब मिडल क्लास को मिलेगा अपना अफोर्डेबल घर

समर न्यूज़ | नई दिल्ली

सरकार समर्थित स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग फंड ने दिसंबर 2025 तक देशभर में अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं में से 61 हजार से अधिक मकानों का निर्माण पूरा किया। इससे 4 लाख लोगों को राहत मिली है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। स्वामी फंड ने 5 दिसंबर 2025 से पहले अपने पूरे निवेश योग्य कोष को प्रतिबद्ध कर दिया है। वर्तमान में इसका पोर्टफोलियो 30 शहरों में फैली 145 से अधिक परियोजनाओं का है, जिससे यह देश का सबसे बड़ा आवासीय तनाव समाधान मंच बन गया है। अब तक 110 परियोजनाओं में लगभग 61,000 मकान पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7,000 से अधिक आवास भी शामिल हैं। मजबूत गवर्नेंस, सक्रिय एसेट मैनेजमेंट और कड़े निगरानी तंत्र के चलते फंड ने 55 पूर्ण और 44 आंशिक निकास भी दर्ज किए हैं। स्वामी फंड से 127 परियोजनाओं में 37,400 करोड़ रुपये की पूंजी अनलॉक की गई है। इसके तहत 90 मिलियन वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल का विकास हुआ, जिसमें 44 फीसदी एलआईजी और एमआईजी आवास शामिल हैं। इस पहल से 36,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए, जिनमें 3,500 स्थायी नौकरियां भी शामिल हैं।

इसके अलावा, फंड से केंद्र और राज्यों को लगभग 6,900 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अटकी परियोजनाओं के पुनरुद्धार से 20 लाख टन सीमेंट और 5.5 लाख मीट्रिक टन स्टील की मांग भी उत्पन्न हुई है। फंड ने अब तक केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 7,000 करोड़ रुपये में से करीब 3,500 करोड़ रुपये वापस भी कर दिए हैं, जो सामाजिक प्रभाव और वित्तीय अनुशासन के संतुलन को दर्शाता है।

बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वामी फंड-2 की घोषणा की थी। 15,000 करोड़ रुपये के इस नए फंड का लक्ष्य एक लाख और आवास इकाइयों को तेजी से पूरा करना है। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड का प्रबंधन एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड कर रहा है। यह फंड रेरा-रजिस्टर्ड, अफॉर्डेबल और मिड-इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अंतिम चरण की फंडिंग उपलब्ध कराता है।

ईस्ट कोस्ट रेलवे ने माल ढुलाई से कमाए 23,000 करोड़

एजेंसी | नई दिल्ली

ईस्ट कोस्ट रेलवे ने मौजूदा वित्त वर्ष 2025–26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 294 दिनों के भीतर माल ढुलाई से 23,000 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक यह लक्ष्य 19 जनवरी को हासिल किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष 2024–25 की तुलना में 27 दिन पहले है, जब यही आंकड़ा 321 दिनों में पूरा हुआ था।

रेलवे अधिकारियों ने इस उपलब्धि को जोन की निरंतर वृद्धि और बेहतर परिचालन दक्षता का नतीजा बताया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह प्रदर्शन माल परिवहन नेटवर्क की मजबूती और समयबद्ध संचालन को दर्शाता है। दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, ईसीओआर की कुल आय 2024–25 में दर्ज 21,543 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025–26 में 23,959 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो 11.21 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इस दौरान यात्री ट्रेनों से होने वाली कमाई भी बढ़कर 1,764.32 करोड़ रुपये से 1,835.91 करोड़ रुपये हो गई। वहीं माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व में बड़ी छलांग देखने को मिली और यह 19,482.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,749.38 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे जोन के मजबूत फ्रेट बेस की पुष्टि होती है।

इसके अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई में भी उल्लेखनीय इजाफा दर्ज किया गया, जो 155.95 करोड़ रुपये से बढ़कर 239.15 करोड़ रुपये हो गई। अधिकारियों का कहना है कि यह विविधीकृत राजस्व स्रोतों और सहायक सेवाओं से मिलने वाली आय में सुधार का संकेत है। फ्रेट लोडिंग के मामले में भी ईस्ट कोस्ट रेलवे ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर 2025 तक जोन ने 209.97 मिलियन टन माल लोड किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 188.64 मिलियन टन था।

पेज 3 एंकर स्टोरी

ओपनएआई का ऐलानः विज्ञापन से नहीं बदलेंगे चैटजीपीटी के जवाब

चैट जीपीटी में फ्री और गो प्लान में शुरू होगी विज्ञापनों की टेस्टिंग

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

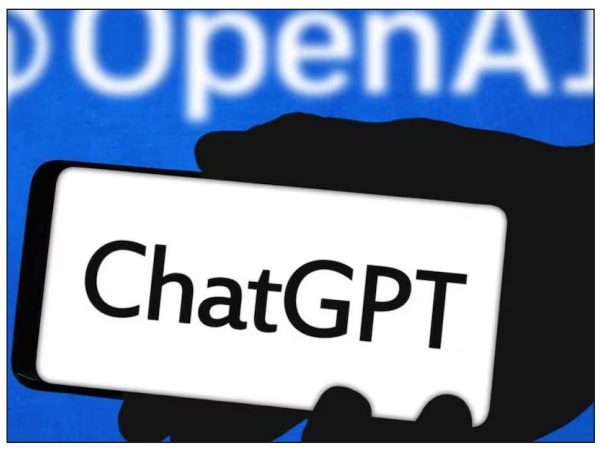

अगर आप चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, तो जल्द ही आपको इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने घोषणा की है कि कंपनी चैटजीपीटी के फ्री और नए गो प्लान में विज्ञापनों की टेस्टिंग शुरू करने जा रही है। हालांकि, ओपनएआई ने स्पष्ट किया है कि इन विज्ञापनों का चैटजीपीटी के जवाबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यूजर्स की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि फ्री और गो (8 डॉलर प्रति माह वाला नया प्लान) में विज्ञापनों की टेस्टिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने कुछ स्पष्ट

सिद्धांत तय किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि हम किसी से भी पैसा लेकर चैटजीपीटी के जवाबों को प्रभावित नहीं करेंगे और यूजर्स की बातचीत विज्ञापन देने वालों से पूरी तरह निजी रहेगी। ऑल्टमैन ने कहा कि बहुत से लोग एआई का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए भुगतान नहीं कर पाते। ऐसे में विज्ञापन आधारित मॉडल से एआई को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

▪ कोई भी कंपनी पैसे देकर जवाबों को प्रभावित नहीं कर सकेगी

ओपनएआई ने साफ किया है कि चैटजीपीटी के जवाब पूरी तरह निष्पक्ष और यूजर के सवाल पर आधारित रहेंगे। कोई भी कंपनी पैसे देकर जवाबों को प्रभावित नहीं कर सकेगी। विज्ञापनों और एआई के जवाबों को अलग-अलग और स्पष्ट रूप से लेबल किया जाएगा, ताकि यूजर को किसी तरह का भ्रम न हो।

▪ यूजर प्राइवेसी रहेगी पूरी तरह सुरक्षित

कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि चैटजीपीटी की चैट किसी भी विज्ञापनदाता के साथ साझा नहीं की जाएगी। यूजर्स की बातचीत पूरी तरह निजी रहेगी और डेटा को विज्ञापन के लिए बेचा नहीं जाएगा। इसके अलावा, यूजर्स को यह कंट्रोल भी मिलेगा कि उनके डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ओपनएआई का कहना है कि विज्ञापन सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि प्राइवेसी से कोई समझौता न हो।

▪ इन प्लान्स में नहीं दिखेंगे Ads

ओपनएआई के अनुसार, Pro, Business और Enterprise प्लान पूरी तरह एड फ्री रहेंगे। इन यूजर्स को किसी भी तरह के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि वह कमाई से ज्यादा यूजर ट्रस्ट और बेहतर अनुभव को प्राथमिकता देती है। ओपनएआई का लक्ष्य एआई को सभी के लिए सुलभ बनाना है। चाहे वह फ्री यूजर हो या पेड। कंपनी ने कहा कि विज्ञापनों को भी इस तरह पेश किया जाएगा कि वे यूजर्स के लिए उपयोगी हों और उनके अनुभव में कम से कम दखल दें।

समाजसेवी रेनू सूद को नम आँखों से दी विदाई

मॉडल टाउन एक्सटेंशन श्मशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार

समर न्यूज़ | लुधियाना

शहर की प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं सरल व्यक्तित्व की धनी स्वर्गीय रेनू सूद का अंतिम संस्कार रविवार को मॉडल टाउन एक्सटेंशन स्थित श्मशान घाट में किया गया । अंतिम संस्कार की रस्में रविवार शाम 5:30 बजे धार्मिक रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरी की गईं। इस अवसर पर परिवारजनों, रिश्तेदारों, मित्रों और समाज के गणमान्य लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोकाकुल वातावरण में सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

श्रीमती रेनू सूद अपने मिलनसार स्वभाव, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक सरोकारों के लिए जानी जाती थीं। उनके निधन से परिवार ही नहीं, बल्कि समाज में भी शोक की लहर है। शोक संतप्त परिवार में पति मदन मोहन सूद, सोनल और नीति सूद, हेमंत सूद, अंजली विने दाऊ, ललित, किरन सूद और नाती-पोते सहित अन्य परिजन शामिल हैं।